साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 30 | प्रति सोमवार इंदौर, 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

अमेरिका युद्धों का तांडव कर मोटी कमाई करो

विश्व पर दादागिरी कर बनो महान

अमेरिका की हथियार बनने वाली सैकड़ो कंपनियां का व्यापार व्यवसाय और कमाई दुनिया में, आमिर की षड़यंत्रकारी विश्व आतंकी व्यापार संगठन जिसका उद्देश्य दुनिया के रसों की सरकारों को खरीद कर वहां के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों पर कब्जा करने किसी भी बहाने अपनी शर्तों थोपने, बातें मानने, के लिए विवश करने न मानने पर युद्ध करवाने पर ही होती है।

आखिर यूक्रेन को युद्ध में अमेरिका ने ही झोंका सफल न होने पर प्रतिबंधों की नौटंकी

उसे क्रिस्पर गुंडागर्दी करने वाले अमेरिका के जिसने 1920 से लेकर अभी तक प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बहाने राष्ट्रों को कब्जे में लेकर वहां अपनी शहनाई रखना सत्ता को हांकने का षड्यंत्र करता है। और जितनी भी अमेरिका के साथ नाटो देश जो है वह अमेरिका के इतनी षड्यंत्र का शिकार हो उसके सहयोगी और राष्ट्र बने हैं। वर्तमान परिपेक्ष में यूक्रेन जो रस से अलग हुआ और रूस का ही एक राष्ट्र है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की इच्छा के विपरीत रूप अपने सामरिक और व्यावसायिक हितो की खातिर अपने ही पड़ोसी राज्य यूक्रेन कोमन करता रहा पर न करने पर वहा के राष्ट्रपति जेलेंस्की जिसने मोटा पैसा अमेरिका से खाया हुआ था। अमेरिका के इसारे पर नाचने के लिए मजबूर हो, रूस से 2 साल से युद्ध कर अपनी बर्बादी कर रहा है। जब अमेरिकाअपनी ईस्पॉरेस में सफल नहीं हो सका तो उसनेरूस पर हाल ही मे 500 से ज्यादा नए प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने पहले भी एक किया था उसे न केवल रस को फायदा हुआ बल्कि अमेरिका और कनाडा देश को भारी घाटे महंगी गैस और क्रूड खरीदने मे उठाना पड़ रहा है।

अमेरिका ने रूस पर लगाए 500 से अधिक नए प्रतिबंध, रूसी विदेश मंत्रालय ने भी लिया कड़ा एक्शन

U.S. Announces 500 New Sanctions Against Russia: अमेरिका ने रूस के करीब 100 फर्मों और व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. यूरोपीय संघ ने भी रूस के करीब 200 कंपनियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है.

U.S. Announces 500 New Sanctions Against Russia: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार (23 फरवरी 2024) को रूस के खिलाफ नए सिरे से 500 से अधिक नए प्रतिबंधों का ऐलान किया है. इसके पीछे की वजह यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने और रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की हिरासत में मौत बताई गई है.

(शेष पेज 6 पर)

सीएजी केंद्रीय कागजी नख दंतहीन जांच गिरोह

सब षड्यंत्र कारियों के इशारे पर नाचने वाली संवैधानिक संस्था

हर मंत्रालय के भ्रष्ट भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी कैग को गिनते ही नहीं

भारत के संविधान की देश के सभी मंत्रालयों के वित्तीय लेन देन राजस्व प्राप्तियां और खर्च के नियमानुसार उपयोग किए जाने और नियंत्रण रखने के लिए भारत का कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या जिसे भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक या कैग नाम से जाना जाता है। जो हर केंद्रीय व राज्यों के शासकीय विभागों और मंत्रालयों में हर वर्ष हर विभाग की जिला स्तर की इकाइयों शाखाओं में अंकेक्षण कर विभागीय लेखो के आवक और उचित खर्चा की नियमित जांच करता है जिसमें उनकी टाइमटर जिले के हर विभाग में मध्य प्रदेश के महालेखाकार विभाग से आती है और लिखो की जांच करती है व उनकी टीम जो आती है।

उनके खाने-पीने और रहने का खर्च संबंधित विभाग का प्रमुख या कार्यालय प्रभारी उनकी 10 15 दिन ठहरने की व्यवस्था खाने-पीने रहने सुरा वह वित्तीय सहयोग के साथ करता है। इसलिए जहां ज्यादा भ्रष्टाचार होता है वहां जानबूझकर बारीकी से जांच करने की अपेक्षा खातों में जो अनियमित तरीके से कार्य किए गए हो उनकी प्रश्नावली तैयार करके उसी प्रश्नावली के बारे में कार्यालय प्रभारी से पूछताछ कर उसकी टिप्पणियां अंकित करता है स्वाभाविक सी बात है उनकी जांच को दबाने के लिए कार्यालय प्रभारी मोटा धन देकर उन भ्रष्टाचारों की जांचो प्रश्नों पर प्राप्त धन के अनुसार समायोजित कर देता है जिससे वह भ्रष्टाचार जो की ग्राम पंचायत से लेकर सभी मंत्रालयों विभागों में किए जाते हैं दबा दिए जाते हैं दूसरी तरफ प्रावेशिक महालेखाकार का कार्यालय सरकारी विभागों के प्रभारी द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाते हैं उनकी जांच कर पता है दूसरी तरफ यथार्थ में भारत की आजादी को 75 साल हो गए परंतु भारत में कागजो में अंकित आंकड़ा कार्यों और लेखों के जांच का कार्य ही किया जा रहा है अभी तक कोई भी भारत में हर विभाग के स्तर पर तकनीकी अंकेक्षण की व्यवस्था जो की हर देश की संवैधानिक आवश्यकता है ताकि जनता से वसूली करगा न केवल सभी प्रकार के कार्यों में उचित तकनीकी गुणवत्ता पूर्वक उपयोग किया गया था नहीं की जांच और अंकेक्षण होना अति आवश्यक है जो अधिकांश विकसित राष्ट्रों में विद्यमान है पर भारत में 75 साल की आजादी के बाद में भी केवल कागजी अंकेक्षण की व्यवस्था ही है जो कि केवल कार्य तक सीमित रहती है परंतु तकनीकी करण में कार्यों में उचित व गुणवत्ता पूर्वक वास्तविकता में साइट पर क्या और कैसा काम हो रहा है इसकी जांच की व्यवस्था न होने के कारण ही वर्तमान में केंद्र राज की सरकारी तीन से पांच गुना की डीपीआर बनवाकर भी 50 से 80% कमीशन खा जाती है

(शेष पेज 6 पर)

सरकार हर दिन करोड़ों विज्ञापन पर करती हैं बर्बाद

सरकारी कर्मियों को वेतन देने नहीं है धन

जनधन बाप की जागीर नहीं, मनमर्जी से लूटो और बर्बाद करो

केंद्र में भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों के साथ मोदी के सत्ता संभालने के बाद से, जनता को भारी भरकम करों यथा कांग्रेस के समय जो चाई सी से ज्यादा वस्तुओं पर कस्टम एक्साइज विक्रय कर वेट वेल्यू एडेड टेक्स के रूप में कर लगता था जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के सार पर थोपे गए माल एवं सेवा कर में अब 1500 से ज्यादा सेवाओं और वस्तुओं पर कर लगता है। उससे पैदा होने वाले बच्चे से लेकर शमशान पहुंचे मृत व्यक्तियों के कफन तक से लूटने वाली सारी केंद्र व राज्य की सरकारें जानबूझकर निर्माण कार्यों के नाम पर 50 से 80% कमीशन हजम करने उस पैसे को 3 से 5 गुना ज्यादा की डीपीआर बनवाने

चाहे फिर उसमें सड़क हो बांधो नहरों तालाबो से लेकर मंदिरों विद्यालयों शिक्षण संस्थान चिकित्सालयों सरकारी भवनों आदि के नव निर्माणों से लेकर पुराने स्थापित भवनों सड़कों बांधों नहरों तालाबों आदि के उन्नयन विस्तार मरम्मत पुन निर्माण नवीनीकरण के नाम पर भी यह हाल जो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय कर रहे थे वह लोग अपने भ्रष्टाचार रूप वसूली छुपाने अपनी पार्टी को अधिकतम धन दिलवाने और सभी सदस्यों को मोटी कमाई कर आर्थिक सामाजिक और नैतिक रूप से मजबूत करने का षड्यंत्र कर रही है इसके साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा तथ्य है वह यह की अपनी भ्रष्टाचारी लूट वसूली जालसाजियां अवैध खनन देश को बेचने वसूली करने मित्रों के लाभ के साथ पिछले 10 सालों में देश की दृश्य और श्रव्य मीडिया अर्थात टीवी चेनलो पर लगातार दिखने वाले फर्जी भ्रामक विज्ञापनों में केंद्र व राज्य सरकारें...

(शेष पेज 6 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

जनता पर भड़ास की अपेक्षा, सामंजस्य, सीमा पर संयोजन की अपेक्षा 56 इंच की लाल आंखें कब?

देश में अगर छल कपट से सत्ता संभाल ही ली थी। तो देश के देश की संपत्तियों और जनता के हितों की सुरक्षा करने का दायित्व था। परंतु पिछले 10 सालों में केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों व पूंजी पतियों की कठपुतली बन नाचने, देश, देश की संपत्तियां मंत्रालयों विभागों उद्योगों सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा विस्तार की अपेक्षा उन्हें कमजोर करने कर्मचारियों अधिकारियों को हटाने वहां की सेवाओं को ठेके पर देने करोड़ों की बेरोजगारी के बाद वहां भर्तीयां न करने, सत्ता के साथ मिले अधोसंरचना को उचित देखभाल न करने वह उसका पैसा हजम करने के लिये विभिन्न बहानों से उनको मोटे कमीशन पर कबाड़ के भाव बेचने लूटने नीलाम करने से खबरदार कर जनहितों को दर किनार कर केवल स्वपोषण में लगे रह जनता को हर तरह से लूटवाने बेरोजगार खबरदार करने का कोई मौका नही छोड़ा। जब जनता और उनके अन्य जनता किसानों व्यापारियों ने इसके विरुद्ध जब-जब आंदोलन किया तब तब उनके खिलाफ पूंजीपतियों को संरक्षण दे, शत्रु से ज्यादा बुरा बर्ताव किया गया और रास्ते में कीलें ठोकी, कंक्रीट की दीवारें उठाई गड्ढे किए मार्ग काटे बिजली इंटरनेट जल आपूर्ति बंद की गई। जबकि वे सारे आंदोलन प्रदर्शन धरने सरकार से बात करने के लिए और समस्या का हल निकाल एक दूसरे के हितों के हित चिंतन में सुझावों का समंजन बैठने के लिए किया गया था विदेश की जनता है देश के हितों के विपरीत कहीं कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन नहीं किया गया इसके विपरीत मूढ़ सत्ताधीशों ने अपने पूंजीपतियों दान कमिश्नदाताओं के हितचिंतन की हठधर्मिता के चलते जिस जनता ने उनको जीतने के लिए वोट दिया और सत्ता में बैठाया उन पर गोलियां बम हवाई हमले किए गए। यह कैसा शासन और किस पर अत्याचार था जिन्होंने अपने वोट देकर आपको सत्ता में बिठाया था या उनके वोटो की जान सजी सही आपने सत्ता को हथिया लिया था। और सप्ताह में आने के बाद देश व जनता के विकास के लिए क्या किया जो भी किया सब अपनी आत्म संतुष्टि और मोटी कमाई के लिए किया। चाहे फिर काशी विश्वनाथ महाकाल अयोध्या का राम मंदिर ओंकारेश्वर का मंदिर के निर्माण की आड़ में अपने नाम वाले शिलालेख लगवा अपने को अमर बनाने की आत्म संतुष्टि के लिए भी हजारों करोड़ का दान हजम कर बनवाने के ठेके मोटे कमीशन पर अपने पूंजीपति मित्रों को दे हजारों वर्ष पुराने ऐतिहासिक ऋषियों मुनियों साधुओं के सैकड़ो मंदिरों मढ़ियों समाधियों को नष्ट कर दिया। बदले में उन पावन तीर्थ क्षेत्रों को अपनी मोटी कमाई के लिए पर्यटन मनोरंजन और मौज मस्ती का का साथ बना दिया। अब महाकालेश्वर काशी विश्वनाथ और श्री राम मंदिरों के दान से प्राप्त धन का सदुपयोग, क्या चारों वेदों, उपनिषदों संहिताओं पुराणों के अध्ययन, उनकी सच्चाइयों, उस लेखन में छिपे गूढ़ रहस्यों को समझने जानने, अनुसंधान प्रयोगों से वर्तमान पीढ़ी के विकास में उपयोग करने के लिए किया जाएगा। या उस दान के धन को अपने बाप की संपत्ति समझ बहानों से हजम कर लिया जायेगा।

दूसरी तरफ अपने देश की जनता से लूटे गए करों से खरीदे गए लाखों करोड़ के कबाड़ छोटे हथियारों मशीनगनों, ड्रोनों रॉकेट स्वचालित राइफलों की गोलियों से आंदोलनकारी जनता किसानों पर डराने धमकाने बरसाये गये। जोकि समस्याओं के लिए आंदोलन कर सम्मानपूर्वक सामने बैठ सुलझाने के लिए आई थी।

जिन सीमाओं की रक्षा के लिए लाखों करोड़ के समय बाधित कबाड़ा हथियार विमान मिसाइल तोपें, ग्रेनेड लॉन्चर्स टियर गैस बॉब शेल्स स्मोक बंब रडार आदि मोटे कमीशन पर खरीदे गए थे उनका उपयोग। 0 साल में अपनी चीन पाकिस्तान से लगी हजारों किलोमीटर लंबी सीमाओं पर कैश को सुरक्षित करने की अपेक्षा खुले में चीनियों से मोटा कमीशन खाकर 56 इंच का दावा करने वाले और चुनाव से पहले चीन को लाल के दिखाने का दम भरने वाले ने ने कभी चीन को अपनी 56 इंच की लाल आंखें नहीं दिखाई और वहां उनको खुली छूट देकर देश की हजारों किलोमीटर लंबी सीमा क्षेत्र में खुले में अतिक्रमण करने हवाई अड्डे रेलवे लाइन सड़के उद्योग गांव, कालोनियां बसाने, बांध नहरें बनाने के बाद इसके बारे में पूरा यूरोपीय देश अमेरिका रूस बरसों से बता चिल्ला रहे हैं। विपक्ष तथ्यों मुद्दों बातों को उठा रहा है। उल्टे ही सुनने समझाने और सैन्य कार्रवाई करने की अपेक्षा वहां बातों से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है। और उसके परिणाम स्वरूप शत्रु चारों तरफ से देश को गिरता चला जा रहा है पर 56 इंचीसीना होने और लाल आंखें दिखाने काटम पर भरने वाले की औकात नहीं हो रही कि उसकी तरफ जोर से चिल्ला कर बात कर सके। तो कैसा डरपोक शासन है, जो जनता पर बम शत्रुओं के साथ हम से सत्ता चला विश्वगुरु बना।

10 साल में कितना बढ़ा आपका महीने का खर्च

पिछले 11 वर्षों में खाने-पीने से लेकर तमाम तरह की चीजों और सेवाओं पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च ढाई गुना तक बढ़ गया है। इस दौरान जहां कुल खर्च में खाने-पीने की चीजों की हिस्सेदारी घटी है, वहीं यात्रा और दूसरी चीजों पर खर्च बढ़ा है। साथ ही, ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच खर्च में अंतर घट गया है। यह जानकारी सरकार के लेटेस्ट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से मिली। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन मिनिस्ट्री के तहत आने वाले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच सर्वे कराया था। यह सर्वे हर 5 साल पर कराया जाता है, लेकिन सरकार ने 2017-18 के सर्वे का नतीजा आंकड़ा में गड़बड़ी की बात कहकर जारी नहीं किया था। ताजा सर्वे में कुल खर्च में फूड आइटम्स की हिस्सेदारी घटने और दूसरी चीजों की बढ़ने का मतलब यह है कि इसके आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की नई सीरीज तैयार करने में मदद मिलेगी। अभी इस इंडेक्स में खाने-पीने की चीजों का वेटेज एजुकेशन, मेडिकल या दूसरे आइटम्स से कहीं ज्यादा है और इनके दाम में कोई भी उतार-चढ़ाव महंगाई के आंकड़ों पर बड़ा असर डालता है।

कम हुआ फासला

ताजा सर्वे के मुताबिक, 2022-23 में ग्रामीण इलाकों में एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3773 रुपये और शहरी इलाकों में 6459 रुपये रहा। 2010-11 में ये आंकड़े 1430 रुपये और 2630 रुपये पर थे। इस तरह रूरल एरिया में खर्च 2.6 गुना और अर्बन एरिया में 2.5 गुना बढ़ गया। इसके साथ ही रूरल-अर्बन गैप घटा है। 2010-11 में शहरों में औसत MPCE गांवों में खर्च से 84% अधिक था। 2022-23 में फासला घटा और यह करीब 71% ही अधिक रह गया है।

बदल रहा खान-पान का पैटर्न

2011-12 में ग्रामीण इलाकों में कुल मासिक खर्च में खाने-पीने की हिस्सेदारी 52.9% थी। 2022-23 में यह 46.4% पर आ गई। शहरों में भी आंकड़ा 42.6% से घटकर 39.2% पर आ गया। गांवों में खाने-पीने पर प्रति व्यक्ति एक महीने का खर्च 1750 रुपये और शहरों में 2530 रुपये रहा। फूड आइटम्स में सबसे ज्यादा खर्च बेवरेजेज और बाहर से खरीदे गए कुक्ड आइटम्स का दिखा रहा है। गांवों में दूध और इससे बनी चीजों पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 314 रुपये और अनाज पर 185 रुपये रहा।

शहरों में इन पर खर्च 466 और 235 रुपये रहा। लेकिन बेवरेजेज और प्रोसेस्ड आइटम्स पर खर्च इनसे भी ज्यादा हो गया है। गांवों में इन पर महीने का प्रति व्यक्ति औसत खर्च 363 रुपये और शहरों में 687 रुपये है। रूरल एरिया में बेवरेजेज और प्रोसेस्ड फूड पर खर्च 2011-12 में कुल MPCE का 7.9% था, जो 2022-23 में 9.6% हो गया। शहरों में यह 9% से बढ़कर 10.6% हो गया है।

खाने से अलग सबसे ज्यादा खर्च किस पर?

खाने-पीने से अलग की चीजों पर गांवों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 2023 रुपये रहा। कुल खर्च में इसकी हिस्सेदारी 54% रही। शहरों में नॉन-फूड आइटम्स पर MPCE 3929 रुपये रहा। कुल खर्च में इसका हिस्सा 61% रहा।

नॉन-फूड आइटम्स में रूरल एरिया में सबसे ज्यादा 285 रुपये का MPCE यात्रा के साधनों पर है। इसके बाद 269 रुपये के साथ मेडिकल खर्च का नंबर है। शहरों में भी कन्वेंएंस पर सबसे ज्यादा 555 रुपये का MPCE है, लेकिन 463 रुपये के साथ डयूरेबल गुड्स दूसरे और 424 रुपये के साथ एंटरटनमेंट तीसरे नंबर पर है। ग्रामीण इलाकों में कन्वेंएंस पर खर्च 2011-12 में कुल खर्च के 4.2% से बढ़कर 2022-23 में 7.6% हो गया। शहरों में यह 6.5% से 8.6% पर पहुंच गया।

टॉप और बॉटम में कितना अंतर

प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के हिसाब से गांवों में जो सबसे निचले 5% लोग हैं, वे 1373 रुपये महीने में गुजारा करते पाए गए। शहरों में इस सबके के लिए एवरेज MPCE 2001 रुपये रहा। सबसे ऊपर के 5% लोगों के लिए गांवों में एवरेज MPCE 10501 रुपये रहा। उनके जैसे ही शहरी लोगों का प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च 20824 रुपये रहा।

राज्यवार क्या है हाल

सबसे ज्यादा MPCE सिक्किम में रहा। वहां ग्रामीण इलाकों के लिए यह 7731 रुपये और शहरी इलाकों में 12105 रुपये रहा। सबसे कम आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 2466 रुपये और 4483 रुपये का रहा। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग खर्च 6576 रुपये और शहरी इलाकों में 8217 रुपये रहा। यूपी में आंकड़ा 3191 रुपये और 5040 रुपये है। बिहार के रूरल एरिया में 3384 रुपये और अर्बन एरिया में 4768 रुपये का आंकड़ा है। महाराष्ट्र के गांवों में MPCE 4010 रुपये और शहरों में 6657 रुपये है।

अलग-अलग सोशल ग्रुप्स की तस्वीर कैसी है

2022-23 के सर्वे के मुताबिक, रूरल एरिया में एक के लिए एवरेज MPCE 3016 रुपये और शहरी इलाकों में 5414 रुपये है। SC के लिए गुजर-बसर पर प्रति व्यक्ति मासिक खर्च का आंकड़ा गांवों में 3474 रुपये और 5307 रुपये का है। OBC के लिए यह 3848 रुपये और 6177 रुपये है। इनके अलावा बाकी लोगों के लिए गांवों में औसत MPCE 4392 रुपये और शहरों में 7333 रुपये है।

ताजा सर्वे में जुड़ा नया पहलू

पहले के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से इस बार एक अलग खास काम हुआ है। विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के जरिए लोगों को खाने-पीने की चीजों से लेकर साइकल, मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्कूटी वगैरह जो कुछ भी मुफ्त मिलता है, उसका असर परंपरागत खर्च में जोड़कर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च का एक अलग आंकड़ा जारी किया गया है। हालांकि इसमें मुफ्त मिलने वाली स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का असर शामिल नहीं किया गया है। इस तरीके से ग्रामीण इलाकों में एवरेज MPCE 3860 रुपये और शहरी इलाकों में 6521 रुपये रहा। इसमें रूरल एरिया में फूड आइटम्स पर औसत खर्च 1832 रुपये और शहरों में 2589 रुपये रहा। नॉन-फूड आइटम्स पर खर्च 2028 रुपये और 3932 रुपये है। इसका मतलब यह है कि समाज कल्याण की योजनाओं के चलते कंजम्पशन ग्रोथ दिख रही है।

सहकार मिलकर करो बंटाधार

सहकारिता में चारों तरफ भ्रष्टाचार का अड्डा

विभागीय ऑडिटर निरीक्षक व अधिकारी ही करते व सिखाते हैं जालसाजियां

सहकारिता यथार्थ में बहुत पावन विचार है। जहां सभी समूह में मिलकर सबके कल्याण, समृद्धि से विकास के लिए सामूहिक स्तर पर प्रयास कर व्यवसायिक यह या बैंकिंग कृषि गृह औद्योगिक उद्यमिता के कार्य करने वालों का सांगठनिक कार्य है। जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी आने को स्तर पर यदि संगठन के पदाधिकारियों की नियत अच्छी है तो बहुत-बहुत सफलतापूर्वक कार्य करता है। पर जहां पदाधिकारियों की नियत साफ नहीं हैवहां यह पदाधिकारियों की जलसा जी और संगठन के उन सदस्यों की बर्बादी का कारण भी बन जाती है। जिसमें प्रदेश का सहकारी विभाग के पंजीयकों से लेकर अंकेक्षक व निरीक्षक अपनी लूट और वसूली करने के लिए सहकारी संगठन के पदाधिकारी को जालसाजी पूर्ण भ्रष्टाचार करने की सलाह देते रहते हैं वही सबसे बड़ा सहकारिता को बर्बाद करने का कारण बन जाता है। जैसा कि अधिकांश सहकारी बैंको साख संस्थाओं से लेकर गृह निर्माण कृषि आदान उपज आदि आने को प्रकार की सहकारी संगठनों में देखने में आता है। यही कारण है विक्रम ग्रामीण सहकारी साख संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को लोकायुक्त के छापे पड़ने के बाद वे करोड़पति अरबपति निकले।

यथार्थ में सभी सहकारी साख बैंकिंग गृह निर्माण रखरखाव उत्पादन आदि की संस्थाओं के पदाधिकारियों को यदि यही सहकारिता विभाग के कर्मचारी अधिकारी पंचक से लेकर अंकेक्षक निरीक्षक तक उन पर नियमित कठोरता के साथ निरीक्षण देखरेख कर सहकारिता के नियमों कानूनों का पालन करवाने पदाधिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखें। तो सभी सहकारी संस्थाएं दीर्घावधि तक सदस्यों की समृद्धि विकास नियमन का कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। और किया जा रहा है। दूसरी तरफ विभाग में अंकेक्षक निरीक्षक सहायक और उपायुक्तों आयुक्त से लेकर मंत्री तक सभी का उद्देश्य जहां वसूली करना हो तो में चाहेंगे क्यों संस्थानों में वहां बैठे पदाधिकारी जालसाजियां करके एक तरफ अपने सदस्यों का शोषण करें तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करके मोटी कमाई करें और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को यथायोग्य भुगतान करते रहें।

शासकीय स्तर पर और कानून के अनुसार सहकारिता के अति पावन और सदस्यों के लिए कल्याणकारी हैं। जिसमें शासकीय स्तर पर सरकार ग्रामीण सहकारी संस्थाओं बैंकों में कृषि के काफी अच्छी कर किए जाते हैपरंतु वहां के जलसा प्रबंधक अपने ही सदस्यों का शोषण करते हुए अनेकों जाल साजियां करने बर्बाद करते हैं।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर सहकारिता विभाग के अधिकांश ऐसे जिम्मेदार पंजीयकों उपयुक्त संयुक्त आयुक्तों से लेकर नीचे तक क्योंकि भ्रष्टाचार से मोटी कमाई होती है इसलिए जानकारी के नाम पर टर्म टू लिखी जाती है और संभागीय स्तर पर बैठे पंजक एवं संयुक्त आयुक्त धारा 63 में अपने अधिक नष्ट उपयुक्त सहायक आयुक्तों के कार्यों में भी धारा 63 के अंतर्गत आवेदक को आयोजित करने की अपेक्षा उल्टे सीधे लंबे चौड़े जवाब में दलीलों भर व देते हैं।

दूसरी तरफ जब सूचना का अधिकार अधिनियम को 18 साल गुजर गए तो आखिर सहकारिता विभाग सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं की जानकारियां उनके पदाधिकारी की जानकारियां और सदस्यों की जानकारियां धारा 4 के अंतर्गत अपनी विभागीय सीटों पर उपलब्ध नहीं करवा पाए और इसीलिए नहीं करवाते हैं ताकि वह आसानी से उनमें भ्रष्टाचार लूट खसोट करते रहे और सारे भ्रष्टाचारों के बाद में भी उनकी जानकारियां सामने लिखना हो इसलिए मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री के कारण से लेकर नीचे तक अधिकांश संस्थाओं की जानकारी अपलोड नहीं की गई है।

सहकारिता के सिद्धान्त

1. पहला सिद्धान्त - स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता

सहकारी सोसायटी ऐसे व्यक्तियों के लिए मुक्त स्वैच्छिक संगठन है, जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ है और सदस्यता के उत्तरदायित्व को बिना किसी लिंग, सामाजिक, जातीय, राजनैतिक तथा धार्मिक भेदभाव के रजामंदी से स्वीकार करते है।

2. दूसरा सिद्धान्त - सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण

सहकारी सोसायटी अपने उन सदस्यों द्वारा नियंत्रित लोकतांत्रिक संगठन है, जो उनकी नीतियों के निर्धारण और विनिश्चयों के संधारण में सक्रियता से भाग लेते हैं। प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित पुरूष तथा स्त्री सदस्यों के प्रति जवाबदार है। प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के सदस्यों को (एक सदस्य एक मत का) समान मताधिकार प्राप्त है तथा सहकारी सोसायटी अन्य स्तरों पर भी लोकतांत्रिक रीति से संगठित होती है।

3. तीसरा सिद्धांत - सदस्यों की आर्थिक भागीदारी

सदस्य अपनी सहकारी सोसाइटियों की पूंजी में अभिदाय करते हैं तथा उसका लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रण करते हैं। उक्त पूंजी का कम से कम एक भाग सहकारी सोसायटी की सार्वजनिक सम्पत्ति होती है। सदस्य प्रायः सदस्यता की शर्त के रूप में अभिदत्त पूंजी पर सीमित प्रतिकार यदि कोई हो, प्राप्त करते हैं। सदस्यगण निम्नलिखित में से किन्हीं प्रयोजनों के लिए अधिशेष आवंटित करते हैं। संभवतः आरक्षित स्थापित उनकी सहकारी सोसाइटी का विकास करने के लिए जिसका कुछ भाग अविभाज्य होगा, सदस्यों को सहकारी सोसाइटियों में उनके संव्यवहारों अनुपात में लाभ पहुंचाना तथा सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य क्रियाकलापों का समर्थन करना।

4. चौथा सिद्धांत - स्वायत्ता तथा स्वाधीनता

सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वशासी आत्मनिर्भर संगठन है। यदि वे सरकार सहित दूसरे संगठनों से करार करते हैं, या बाह्य स्त्रोतों से पूंजी जुटाते हैं तो वे ऐसा अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपनी सहकारी सोसाइटियों की स्वायत्ता बनाये रखने के लिए करते हैं।

5. पाचवां सिद्धांत - शिक्षा प्रशिक्षण तथा जानकारी

सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं, जिससे वे अपनी सहकारी सोसाइटियों के विकास में प्रभावी योगदान कर सकें। वे जन सामान्य विशिष्टतः युवा वर्ग एंव नेतृत्व को सहकारिता की प्रवृति तथा लाभ की जानकारी देवें।

6. छटवां सिद्धांत - सहकारी सोसाइटियों में सहयोग

सहकारी सोसाइटी स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से कार्य करते हुए अपने सदस्यों की प्रभावी सेवा करती है और सहकारी आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है।

7. सातवां सिद्धांत - समुदाय के लिए सरोकार

सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदायों के स्थिर विकास के लिए कार्य करती है।

योजनाएं

1. शून्यी प्रतिशत ब्याजदर पर अल्पकालीन कृषि ऋण

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रू. 19000.00 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 21.01.2023 तक राशि रू. 16430.29 करोड़ का अल्पकालीन फसल ऋण वितरण किया जा चुका है।

2. नवाचार

सहकारिता में नवाचार को एक अभियान के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवाचार अन्तर्गत प्रदेश में अनेक नवीन क्षेत्रों में यथा पर्यटन, ई-रिक्शा, परिवहन, सेवाप्रदाता, जैविक कृषि, रहवासी, सामाजिक वानिकी एवं उद्यानिकी, श्रम ठेका, कड़कनाथ मुर्गीपालन, भंडारण, कम्प्यूटर प्रोद्यागिकी, गणवेश, सुरक्षा, महिला गृह उद्योग,पेन्टर आर्टिस्ट सहकारी संस्था, रूद्र सर्प विष विकर्षण एवं अनुसंधान समिति कुल 814 समितियों का पंजीयन किया गया है। जिसमें राज्य स्तरीय 3 फेडरेशन- म.प्र.राज्य सहकारी पर्यटन संघ मर्या., म.प्र.राज्य सहकारी भण्डार गृह संघ मर्या., म.प्र.जनऔषधि उत्पादन एवं विपणन संघ मर्या., तथा म.प्र. राज्य श्रमिक सहकारी संघ मर्या., भोपाल का पंजीयन किया गया है। अन्य क्षेत्रों में संघ के गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

3. आत्म निर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर भारत सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "आत्मनिर्भर भारत" के अन्तर्गत "कृषि अधोसंरचना निधि" (ए.आई.एफ) के मध्यम से लंबी अवधि हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध करवाकर सहकारी क्षेत्र में संस्थाओं के उन्नयन करने तथा कृषि अधोसंरचना निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही की जा रही है।आत्मनिर्भर भारत योजना अन्तर्गत कृषि अधोसंरचना कोष से पैक्स, विपणन एवं बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा शासकीय प्रति भूति पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत म.प्र. में पैक्स द्वारा 304 डी.पी.आर राशि रू. 90.78 करोड़ की तैयार की जाकर जिला बैंकों द्वारा 255प्रोजेक्ट रू. 64.71 करोड़ के स्वीकृत किये गये है, एवं नाबार्ड से 254 समितियों के 60.69 करोड़ रू. पुर्न वित्त हेतु स्वीकृत किये गये है।

"आत्मनिर्भर म.प्र." योजना के अन्तर्गत पैक्स संस्थाओं में कृषकों के लिए ऋण, विपणन एवं अन्य सेवायें प्रदान करने हेतु, "सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएससी)" की स्थापना हेतु 03 वर्षीय कार्य योजना तैयार की गईहै। योजनान्तर्गत पैक्स में 4105 "सामान्य सुविधा केन्द्र" प्रारंभ किये जा चुके है। इन सामान्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आलोच्य वर्ष में 1,44,900 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है। सामान्य सुविधा केन्द्रों द्वारा राशि रू. 5,80,300 की आय अर्जित की गई है।

4. ई-गवर्नेंस क्षेत्र में सहकारिता विभाग

विभाग द्वारा वेब पोर्टल म.प्र. राज्य सहकारी पोर्टल (ई-कॉआपरेटिव) का संचालन किया जा रहा है। जिसमें विभाग की सामान्य सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुचाये जाने वाले का प्रयास किया गया है।

ई-गवर्नेंस क्षेत्र की दिशा में विभाग द्वारा नवीन सहकारी संस्थाओं के

ऑनलाइन पंजीयन हेतु मैप आई.टी. की सहायता से एक वेब पोर्टल एकीकृत सहकारी प्रबंधन सूचना प्रणाल URL-https://icmis.mp.gov.in/ (विकसित किया गया है। जिसमें सहकारी संस्थाओं के पंजीयन हेतु आवेदन से लेकर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रिन्ट होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया एन्ड टू एन्ड ऑनलाइन है। साथ ही मैप आई.टी. की सहायता से सहकारी न्यायालयीन प्रणाली की मॉनिटरिंग हेतु Cooperative Judicial Court Management System (CJCMS) https://cjcms.mp.gov.in भी विकसित किया गया है। विभागीय ई-कॉओपरेटिव से प्रदेश स्तर की सहकारी संस्थाओं का सिस्टम आधारित विभागीय अंकेक्षकों को अंकेक्षण आवंटन तथा सहकारी बैंकों के वैधानिक अंकेक्षण हेतु प्रति वर्ष सनदी लेखापालों का ऑनलाइन पैनल तैयार किया जाता है व चयन की प्रक्रिया पूर्णतः मानवीय हस्तक्षेप विहीन है।

राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस- भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं "राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस परियोजना" के अंतर्गत म.प्र. की समस्त जिला स्तरीय सहकारी समितियों की प्रविष्टी की जाकर सहकारी संस्थाओं का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया गया है। जिसमें राज्य की संस्थाओं की न केवल पूरी प्रविष्टी की गई अपितु संपूर्ण पैक्स - पंचायत कवरेज को भी दर्ज किया गया है।

विभाग द्वारा विभिन्न जी.टू.सी. एवं जी.टू.जी. सेवाओं अंतर्गत विभाग के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता लाने का प्रयास किया गया है। ईज ऑफ डूइंग अवधारणा के तहत विभाग अपनी अधिकारिक सेवाओं को ई-प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में अग्रसर है। इस दिशा में विभाग को भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय की 54 पहलो में 53 पहल के अंतर्गत पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

5. सहकार से समृद्धि

भारत सरकार की "सहकार से समृद्धि" योजनान्तर्गत 54 प्रमुख पहलो में से प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आदर्श उपविधियों के रूप में समस्त 4534 पैक्स में बी-पैक्स से संबंधित उपविधियां लागू की गई। बी-पैक्स अंतर्गत इन समितियों के आधारभूत ढांचा को सुदृढ़ करना तथा इनके व्यवसाय में वृद्धि हेतु अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे की एलपीजी वितरण, डीजल/ पेट्रोल के आउटलेट खोलना, जनऔषधि वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना, विश्व की महानतम अनाज भंडारण योजना आदि कार्यों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत अन्य पहलुओं पर भी विशिष्ट क्षेत्र चिन्हित किए जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

साप्ताहिक समय माया

काली मिर्च

फायदे, उपयोग और औषधीय गुण

भारत में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां काली मिर्च का प्रयोग नहीं होता हो। यह मसालों की रानी मानी जाती है। चाहे हम कोई भी सब्जी बनाएं। सब्जी सूखी हो या रसेदार या फिर नमकीन से लेकर सूप आदि तक, हरेक व्यंजन में काली मिर्च का प्रयोग जरूर होता है। भोजन में काली मिर्च का इस्तेमाल केवल स्वाद के लिए नहीं किया जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायकहै। काली मिर्च एक अच्छी औषधि भी है। लंबे समय से आयुर्वेद में इसका औषधीय प्रयोग होता रहा है। वास्तव में काली मिर्च के औषधीय गुणों के कारण ही इसे भोजन में शामिल किया जाता है। काली मिर्च का प्रयोग रोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। काली मिर्च के काफी अधिक औषधीय लाभ हैं। यह वात और कफ को नष्ट करती है और कफ तथा वायु को निकालती है। यह भूख बढ़ाती है, भोजन को पचाती है, लीवर को स्वस्थ बनाती है और दर्द तथा पेट के कीड़ों को खत्म करती है। यह पेशाब बढ़ाती है और दमे को नष्ट करती है। तीखा और गरम होने के कारण यह मुँह में लार पैदा करती है और शरीर के समस्त स्रोतों से मलों को बाहर निकाल कर स्रोतों को शुद्ध करती है। इसे प्रमाथी द्रव्यों में प्रधान माना गया है। आइए जानते हैं कि आप बीमारियों को ठीक करने के लिए काली मिर्च का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

क्या है काली मिर्च

काली मिर्च एक औषधीय मसाला है। इसे काली मिर्च भी कहते हैं। यह दिखने में थोड़ी छोटी, गोल और काले रंग की होती है। इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी लता बहुत समय तक जीवित रहने वाली होती है। यह पान के जैसे पत्ते वाली, बहुत तेजी से फैलने वाली और कोमल लता होती है। इसकी लता मजबूत सहारे से लिपट कर ऊपर बढ़ती है।

एक वर्ष में इसकी लगभग दो उपज प्राप्त होती हैं। पहली उपज अगस्त-सितम्बर में और दूसरी मार्च-अप्रैल में। बाजारों में दो प्रकार की मिर्च बिकती है– सफेद मिर्च और काली मरिच। कालीमिर्च की तासीर आयुर्वेद के अनुसार न शीत है और न उष्ण; लेकिन कहीं-कहीं पर इसका उष्ण तासीर का भी बताया गया है।

कुछ लोग सफेद मिर्च को काली मिर्च की एक विशेष जाति मानते हैं। कोई सहिजन के बीजों को ही सफेद मिर्च मान लेते हैं। सफेद मिर्च काली मिर्च का ही एक अलग रूप है। आधे पके फलों की काली मिर्च बनती है तथा पूरे पके फलों को पानी में भिगोकर, हाथ से मसल कर ऊपर का छिल्का उतार देने से वह सफेद मिर्च बन जाती है। छिल्का हट जाने से इसकी गरम तासीर कुछ कम हो जाती है तथा गुणों में कुछ सौम्यता आ जाती है।

काली मिर्च के औषधीय प्रयोग से लाभ...

काली मिर्च का भोजन में प्रयोग करने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, ठंड के दिनों में बनाए जाने वाले सभी पकवानों में काली मिर्च का उपयोग किया जाता है ताकि ठंड और गले की बीमारियों से रक्षा हो सके। काली मिर्च नपुंसकता, रजोरोध यानी मासिक धर्म के न आने, चर्म रोग, बुखार तथा कुष्ठ रोग आदि में लाभकारी है। आँखों के लिए यह विशेष हितकारी होती है। जोड़ों का दर्द, गठिया, लकवा एवं खुजली आदि में काली मिर्च में पकाए तेल की मालिश करने से बहुत लाभ होता है।

विभिन्न रोगों में इसका उपयोग करने की विधि यहाँ प्रस्तुत हैः-

सिर दर्द दूर करे

- एक काली मिर्च को सुई की नोक पर लगाकर उसे दीपक में जला लें। उसमें से निकलने वाले धुएं को सूंघने से सिरदर्द में आराम होता है। इससे हिचकी भी बंद होती है। सिर दर्द में काली मिर्च के फायदे बहुत लाभकारी साबित होते हैं।
- भृंगराज के रस अथवा चावलों के पानी के साथ काली मिर्च को पीसकर माथे पर लेप करने से आधासीसी का दर्द यानी माइग्रेन भी ठीक होता है।

डैंड्रफ या रूसी भगाए

- बालों में जुँ हो जाने पर 10-12 सीताफल के बीज और 5-6 काली मिर्चों को पीस कर सरसों के तेल में मिला लें। इसे रात में सोने से पहले बालों की जड़ों में लगा लें। सुबह बाल धोकर साफ कर लें। जुं नष्ट हो जाएगी।
- सिर के बाल यदि झड़ते हों तो काली मिर्च को प्याज व नमक के साथ पीसकर लगाने से लाभ होता है।

खाँसी-जुकाम दूर करे

- काली मिर्च के 2 ग्राम चूर्ण को गर्म दूध तथा मिश्री के साथ पी लेने अथवा इसके 7 दाने निगलने से जुकाम तथा खाँसी में लाभ होता है।
- 50 ग्राम दही, 15-20 ग्राम गुड़ और एक-डेढ़ ग्राम काली मिर्च चूर्ण को मिला लें। इसे दिन में 3-4 बार सेवन करने से जुकाम में लाभ होता है।

आँखों की बीमारी में फायदेमंद

- काली मिर्च को दही के साथ पीसकर आँखों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी में लाभ होता है। इसे अत्यन्त सावधानीपूर्वक बाहर-बाहर ही लगाएं।
- आँखों की रौशनी बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह आधा से 1 ग्राम तक काली-मिर्च में 1 चम्मच घी तथा आवश्यकतानुसार मिश्री मिलाकर चाटें। बाद में दूध पीएं। इससे आँखों की बीमारी में लाभ होता है।
- आँखों की पलकों पर अगर फुंसी हो जाए तो काली मिर्च को पानी में घिसकर लेप करने से फुंसी पककर फूट जाती है।
- काली मिर्च के आधे ग्राम चूर्ण को एक चम्मच देशी घी में मिलाकर खाने से अनेक प्रकार के नेत्र रोगों का खात्मा होता है।

दांत दर्द में आराम दिलाये

- काली मिर्च के 1-2 ग्राम चूर्ण को 3-4 जामुन या अमरूद के पत्तों या पोस्तदानों के साथ पीस लें। इससे कुल्ला करने से दांत दर्द ठीक होता है।
- गले के रोग व आवाज बैठ जाने पर भी यह प्रयोग लाभप्रद है।
- सेंधा नमक, काली मिर्च, शहद तथा नीबू के रस को मिला कर तालू पर लेप करने से मुँह के छाले में लाभ होता है।

दमा-खाँसी का इलाज

- 2-3 ग्राम काली मिर्च चूर्ण को शहद और घी (असमान मात्रा में) में मिला लें। इसे सुबह-शाम चाटने से सर्दी, सामान्य खाँसी, दमा और सीने का दर्द मिटता है। इससे फेफड़ों में जमा कफ निकल जाता है।
- 200 मिली गाय के दूध में 2 ग्राम काली मिर्च चूर्ण को पकाकर पिलाने से दमा-खाँसी में लाभ होता है।
- यदि खाँसी बार-बार उठती हो, भोजन निगलने में कष्ट हो तो दिन में 2-3 बार काली मिर्च के हल्के काढ़े से कुल्ला करें।
- काली मिर्च चूर्ण 2 भाग, पीपली चूर्ण 2 भाग, अनार की छाल 4 भाग तथा जौ एक भाग का चूर्ण बना लें। इसमें 8 भाग गुड़ मिलाकर 1-1 ग्राम की गोलियाँ बना लें। इसे दिन में तीन बार सेवन करने से गले का दर्द (कष्टदायक खाँसी) में लाभ होता है।
- गले की खराश व खाँसी में 2-3 काली मिर्च मुंह में रखकर चूसने मात्र से लाभ होता है।

दस्त रोकने के लिए करें प्रयोग

- एक भाग काली मिर्च की चूर्ण तथा एक भाग भुनी हींग को अच्छी तरह खरल कर लें। इसमें दो भाग शुद्ध देशी कपूर मिलाकर 125 मि.ग्राम की गोलियाँ बना लें। इसे आधे घंटे के अंतर से 1-1 गोली देने से हैजे की शुरुआती (प्रथम) अवस्था में लाभ होता है।
- काली मिर्च की चूर्ण 1 ग्राम तथा भुनी हींग 1 ग्राम को अच्छी तरह खरल कर लें। इसमें 3 ग्राम अफीम मिलाकर शहद में घोटकर 12 गोलियाँ बना लें। कर 1-1 गोली 1 घंटे के अंतर से दें। बहुत समय तक न दें। इससे पेचिश में भी अत्यन्त लाभ होता है। अफीम मिले होने के कारण इसका प्रयोग सावधानी से करें।
- काली मिर्च चूर्ण 1/2 ग्राम, हींग 1/4 ग्राम तथा अफीम 100 मिग्रा को मिला लें। इसे जल या शहद के साथ सुबह, दोपहर तथा सायं सेवन करने से पेचिश में लाभ होता है।

पेट के रोगों में फायदेमंद

- 2-3 ग्राम काली मिर्च चूर्ण को 1 कप छाछ के साथ सुबह खाली पेट लेने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं।
- 8-10 काली मिर्च को 5-7 ग्राम शिरीष के पत्तों के साथ पीसकर छान लें। इसे पीने से गैस के कारण होने वाले पेट दर्द और पेट फूलने में आराम मिलता है।
- एक कप पानी में आधा नीबू निचोड़ लें। इसमें 5-6 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर भोजन के बाद सुबह-शाम पीने से पेट की गैस, भूख का घटना-बढ़ना आदि में लाभ होता है।
- काली मिर्च के चूर्ण के साथ बराबर भाग सोंठ, पीपली, जीरा और सेंधा नमक मिला लें। 1-1 ग्राम की मात्रा में, भोजन के बाद गर्म जल के साथ लेने से अपच तथा बदहजमी में लाभ होता है।
- काली मरिच, सोंठ, पीपल तथा हरड़ चूर्ण मिलाकर शहद के साथ देने से अथवा इसके काढ़े को पीने से अपच तथा पेट की गैस में लाभ होता है।

बवासीर में फायदा

- दो ग्राम काली मिर्च चूर्ण, 1 ग्राम भुना जीरा, 15 ग्राम शहद या शक्कर को मिला लें। दो बार छाछ के साथ या गर्म जल के साथ सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है।
- काली मिर्च चूर्ण 25 ग्राम, भुना जीरा चूर्ण 35 ग्राम और शुद्ध शहद 180 ग्राम को मिला लें। इसे अवलेह (चटनी) बनाकर रखें। इस अवलेह को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में दिन में तीन बार सेवन करें। इससे बवासीर में फायदा होता है।
- काली मिर्च और जीरे के मिश्रण में सेंधा नमक मिला लें। इस दिन में दो बार छाछ के साथ 3-4 मास तक सेवन करते रहने से बवासीर में आराम मिलता है। इससे कमजोरी या वृद्धावस्था के कारण हुए बवासीर या गुदभ्रंश (कौंच निकलना) ठीक होते हैं। इससे पाचन व जठराग्नि ठीक रहती है। कब्ज और पेट की गैस में भी यह प्रयोग लाभप्रद है।
- एक ग्राम काली मिर्च चूर्ण को शहद के साथ दिन में तीन बार प्रयोग करें। इससे गुदा का बाहर निकलना बंद हो जाता है।

मूत्र रोग में फायदेमंद

- एक ग्राम काली मिर्च और बराबर मात्रा में खीरा या ककड़ी के बीज को 10-15 मिली पानी के साथ पीस लें। इसमें मिश्री मिलाकर छानकर पिलाएं। इससे पेशाब में जलन तथा पेशाब से दर्द आदि की परेशानी में लाभ होता है।

नपुंसकता दूर करे

- एक गिलास दूध में 8-10 काली मिर्च को डाल लें। इसे अच्छी तरह उबालकर, सुबह-शाम नियमपूर्वक सेवन करने से वीर्य विकार ठीक होता है। गर्मी के मौसम में मात्रा कम की जा सकती है।

घाव सुखाने के लिए करें उपयोग

- काली मिर्च को पानी में पीसकर फोड़े-फुंसियों व सूजन पर लेप करने से घाव सुख जाता है। इससे घाव जल्दी भर जाते हैं और सूजन दूर होती है।

हिस्टीरिया में फायदेमंद

- 3 ग्राम वच चूर्ण में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिला लें। इसे खट्टी दही के साथ सुबह खाली पेट सेवन करने से हिस्टीरिया में लाभ होता है।

चेहरे के लकवा में लाभकारी

- अर्दित रोग यानी फेशियल पैरालिसिस में चेहरे के अंगों में लकवा मार देता है। यदि जीभ में जकड़न हो तो मिर्च के चूर्ण को जीभ पर घिसने से लाभ होता है।
- काली मिर्च चूर्ण को किसी भी वातशामक तेल में मिला लें। इसे लकवाग्रस्त अंग पर मालिश करने से बहुत लाभ होता है। काली मिर्च खाने के फायदे चेहरे पर लकवा मारने में बहुत फायदेमंद होता है।

शारीरिक ताकत बढ़ाए

- कमजोरी आलस्य, उदासीनता आदि दूर करने के लिए काली मिर्च के 4-5 दाने, सोंठ, दालचीनी, लौंग और इलायची थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिला लें। इसे चाय की तरह उबाल लें। इसमें दूध और शक्कर मिलाकर पीने से लाभ होता है। कमजोरी दूर करने में काली मिर्च के औषधीय गुण बहुत फायदेमंद साबित होते हैं।

बुखार उतारे

- 1-3 ग्राम काली मिर्च चूर्ण में आधा लीटर पानी और 2.0 ग्राम मिश्री मिलाकर आठवाँ भाग शेष रहने तक उबाल कर काढ़ा बना लें। इसे सुबह, दोपहर तथा शाम पिलाने से साधारण बुखार यानी वायरल फीवर में लाभ होता है।
- 5 दाने काली मरिच, अजवायन एक ग्राम और हरी गिलोय 10 ग्राम, सबको 250 मिली पानी में पीस, छानकर पिलाने से तेज बुखार में लाभ होता है।
- एक ग्राम काली मिर्च चूर्ण को शहद के साथ दिन में तीन बार सेवन करने से गैस के कारण होने वाला बुखार तथा पेट दर्द दूर होता है ।

शरीर का पोषण बढ़ाए

- कालीमिर्च में आयुर्वेद के अनुसार ऐसे गुण होते है जो कि शरीर के पोषण को बढ़ावा देते है विशेष रूप से दीपन का गुण जो कि पाचकाग्नि को बढ़ा कर शरीर को पोषण देने में मदद कर करता है।

वजन कम करने में फायदेमंद

- अगर आप बढ़े हुए वजन से परेशान है तो, कालीमिर्च का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार कालीमिर्च में पाये जाने वाला एक तत्व चर्बी यानि फैट को कम करने में मदद करता है।

गठिया का दर्द कम करे

- गठिया दर्द को कम करने में कालीमिर्च एक अच्छा उपाय है, क्योंकि कालीमिर्च में आयुर्वेद के अनुसार वात को कम करने का गुण होता है। जिसके वजह से गठिया का दर्द को कम होने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में गठिया को वात प्रधान रोग माना जाता है।

कैंसर के इलाज में फायदेमंद

- कालीमिर्च का सेवन कैंसर को फैलने से रोकने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि कालीमिर्च में एंटी- कैंसर का गुण पाया जाता है जो कि कैंसर को फैलने से रोकने में मदद करता है।

अवसाद या डिप्रेशन को करे कम

- कालीमिर्च का सेवन आपको डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि रिसर्च के अनुसार इसमें पाये जाने वाले एल्कलॉइड में एंटी -डिप्रेशन का गुण पाया जाता है।

विटिलिगो के इलाज में फायदेमंद

- विटिलिगो की समस्या में कालीमिर्च का उपयोग फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार कालीमिर्च का जब बाहरी रूप से प्रयोग किया जाता है तो ये पिगमेंटेशन को बढ़ाकर रोगों के लक्षणों को कम करने में मदद करता है।

काली मिर्च कहाँ पाई या उगाई जाती है

काली मिर्च के पौधे का मूल स्थान दक्षिण भारत ही माना जाता है। पूरी दुनिया में काली मिर्च की पैदावार सबसे ज्यादा भारत में ही होती है। भारत से बाहर इंडोनेशिया, बोर्नियो, इंडोचीन, मलय, लंका और स्याम इत्यादि देशों में भी इसकी खेती की जाती है। कुछ जन प्रदेशों में यह स्वयं उत्पन्न होती है, लेकिन दक्षिणी भारत के उष्ण और आर्द्र भागों में काली मिर्च की बेल बोई जाती है। काली मिर्च के कारण ही एक समय भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था।

इस्तेमाल के लिए काली मिर्च के उपयोगी हिस्से

फल

काली मिर्च के सेवन की मात्रा

चूर्ण – 1-2 ग्राम

औषधि के रूप में काली मिर्च का इस्तेमाल से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें।

काली मिर्च से नुकसान

इन रोगों की अवस्था में काली मिर्च का उपयोग नहीं करना चाहिए:-

- **घाव**
- **एसिडिटी**
- **खूनी बवासीर**
- **गर्भावस्था की अवस्था**

काली मिर्च से जुड़े अक्सर पूछे जाने सवाल ..?

1- क्या सुबह काली मिर्च का सेवन करना फायदेमंद होता है?

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार सुबह के समय काली मिर्च का सेवन करना फायदेमंद है। खासतौर पर सर्दियों के मौसम में सुबह काली मिर्च डाली हुई चाय का सेवन करने से कफ दूर होता है। इससे कफ को कम करने का गुण होता है इस वजह से काली मिर्च वाली चाय पीने से गले को आराम मिलता है।

2- क्या काली मिर्च का काढ़ा कोरोना से बचाव में कारगर है?

कोविड-19 से बचाव और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने कई दिशानिर्देश जारी किए हैं और लोगों को हर्बल काढ़ा पीने की सलाह दी है। इस हर्बल काढ़े का एक मुख्य घटक काली मिर्च भी है। विशेषज्ञों के अनुसार काली मिर्च का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में मदद करता है।

3- खांसी से आराम पाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल कैसे करें?

यदि आप खाँसी की समस्या से परेशान है और कई घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी खांसी से आराम नहीं मिल रहा है तो काली मिर्च का उपयोग करें। काली मिर्च खांसी दूर करने का अचूक उपाय है। इसके लिए काली मिर्च के पाउडर में थोड़ा सा शहद मिलाकर उसका सेवन करें। काली मिर्च और शहद दोनों में ही प्रकुपित कफ को शांत करने का गुण पाया जाता है। इसलिए इसके सेवन से बहुत जल्दी खांसी से आराम मिलता है।

4- सर्दी-जुकाम से आराम पाने के लिए काली मिर्च का उपयोग कैसे करें?

जाड़ो में अक्सर लोग सर्दी-जुकाम से परेशान रहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी-जुकाम होने पर दवा लेने की बजाय घरेलू उपाय अपनाना ज्यादा कारगर होता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप सर्दी-जुकाम से परेशान है तो चाय में काली मिर्च डालकर उसका सेवन करें। काली मिर्च युक्त चाय का स्वाद भी बेहतर होता है और इसकी गर्म तासीर सर्दी-जुकाम के लक्षणों को कम करने में मदद करती है।

5- क्या काली मिर्च के सेवन से इम्यूनिटी बढ़ती है?

काली मिर्च का सेवन न केवल कफ की समस्या को कम करता है बल्कि इसका सेवन रोगों से लड़ने की शक्ति यानि इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप काली मिर्च का सेवन कई तरह से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका सेवन मसाले के रूप में कर सकते हैं या फिर चाय में डाल कर या शहद में मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है।

सब षड्यंत्र कारियों के इशारे पर नाचने वाली संवैधानिक संस्था

पेज 1 का शेष

और गुणवत्ता ही कम होने के साथ भारी आर्थिक जनधन की हानि भी उठानी पड़ती है जैसा कि आपने देखा मध्य प्रदेश में ही भवनों स्टेशनों बस स्टैंड चिकित्सालयों विद्यालयों पुल पुलिया सड़कों नहरों बांधों का निर्माण उन्नयन विस्तार मरम्मत पुनःनवीनीकरण हुआ उसमें तकनीकी अंकेक्षण की व्यवस्था न होने के कारण जनधन की बर्बादी के साथ उसकी कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। उसका लाभ भी जनता को नहीं मिला बादल में 50 से 80% कमीशन वहां बैठे इंजीनियरों डॉक्टर कृषि वैज्ञानिकों अधिकारीयो द्वारा मनमर्जी से क्योंकि कोई भी तकनीकी अंकेक्षण गुणवत्ता की जांच डीपीआर आदि की जांच से लेकर मैदान में वास्तविकता में इस गुणवत्ता वचनेवास्तविक खर्च का अनुमान लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम पालिकाओं जिलाधीश कार्यालयों में बैठे गैर तकनीकी पटवारी तहसीलदार निरीक्षकों से लेकर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों ने खूब मनमर्जी कर जनता का धन बर्बाद कर मोटा कमीशन हजम करने पर तुली है। और उसमें का गया प्रदेश का महालेखाकार का कोई सीधा हाथ लिया टिप्पणी नहीं हो पाती क्योंकि वह सब कागजी शेर है जो कागज को देखकर ही गुर्राते बताते और समझाते है।

भारत की केंद्र सरकार के साथ राज्यों की सरकारों को चाहिए कि वहमुख्य तकनीकी परीक्षण करी अपेक्षा भी सभी शासकीय विभागों की तकनीकी अंकेक्षण परीक्षण और गुणवत्ता की जांच के लिए जितने भी प्रदेश के सभी विभागों से रिटायर्ड इंजीनियर डॉक्टर ऑडिटर वैज्ञानिक आदि की संस्था बनाकर उनके अनुभवों का लाभ ले जनधन से किया जा रहे कार्यों का तकनीकी परीक्षण कर वह शासन को बताए ताकि जनधन की बर्बादी को रोकने के साथ आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को उसका समुचित और पूरा लाभ मिल सके जिसकी मैं पिछले 20 सालों से मांग कर रहा हूं। सीएजीकी ऊर्जा विभाग के बारे में जो रिपोर्ट है वह यहां लगाई जा रही है।

विश्व पर दादागिरी कर बनो महान

पेज 1 का शेष

अमेरिकी प्रेसिडेंट के मुताबिक इस नियम के तहत नवलनी की मौत के जिम्मेदार लोगों और रूसी सेना को निशाना बनाया गया है

आक्रामकता को आक्रामकता दिखाना पड़ रहा है भारी

बाइडन के बयान के अनुसार ये प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं कि दूसरे देश पर आक्रामकता दिखाना और घरेलू स्तर पर दमन करना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भारी कीमत चुकाने जैसा है. अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा रूस के खिलाफ यह प्रतिबंध नवलनी के निधन के बाद आए हैं. हाल ही में पुतिन के कट्टर आलोचक नवलनी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी.

100 फर्मों और व्यक्तियों पर लगे कड़े प्रतिबंध

अमेरिका ने रूस के करीब 100 फर्मों और व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. यही नहीं यूरोपीय संघ ने भी रूस के करीब 200 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया है.

रूसी विदेश मंत्रालय का आया बयान

अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए लगाए जाने के बाद रूसी विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है. जारी किए गए बयान में बोला गया है कि रूस में प्रवेश से प्रतिबंधित यूरोपीय संघ के अधिकारियों और नेताओं की सूची को और बढ़ा दिया गया है.

पहले योजना बना रहा था अमेरिका

इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि यूक्रेन पर लगातार हमले को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका रूस पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है. वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए बयान में बताया गया था कि अमेरिका, रूस और उसके समर्थकों एवं उसकी युद्ध मशीनों पर कड़ा प्रहार करने वाले है.

पटवारी घोटाला महाआंदोलन अब 28 फरवरी को भोपाल में, अंतिम मौका और लड़ाई का दिया नारा

पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप लगा रहे छात्र, उम्मीदवारों ने अब एक बार फिर सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। रविवार को नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने बैठक कर फैसला लिया कि यहां-वहां प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा और आंदोलन सीधे भोपाल में करना होगा। ताकि सामान्य प्रशासन विभाग और ईएसबी तक बात जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। तय किया गया कि 28 फरवरी को भोपाल में पटवारी घोटाला महाआंदोलन किया जाएगा और इसे अंतिम मौका और अंतिम लड़ाई कहा गया है।

यूपी में सिपाही भर्ती रद्द होने के बाद जोश में युवा

यूपी में भी बीजेपी सरकार है और वहां सिपाही भर्ती परीक्षा पर लगे आरोप और आंदोलन के बाद योगी सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दोबारा छह माह में परीक्षा कराने का आदेश दिया है। इस खबर के बाद फिर से छात्र, उम्मीदवार जोश में हैं, और कह रहे हैं कि जब वहां हो सकता है तो मप्र में भी परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो सकती है? इसलिए फिर से आंदोलन करना चाहिए।

इन मांगों को लेकर जाएंगे भोपाल

एनईवायू ने कहा कि मप्र पटवारी भर्ती परीक्षा में लगभग 50 फीसदी पदों पर फर्जीवाड़ा हुआ है और यदि आज इसे नहीं रोका गया तो यह प्रथा बन जाएगी।

भोपाल चलो आंदोलन के लिए मुख्य मांग है कि-

1- पटवारी फर्जी नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगाई जाए

2- पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए

3- मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में तकनीकी विशेषज्ञों की एसआईटी गठित हो

4- फर्जीवाड़ा पाए जाने पर पटवारी भर्ती को रद्द करके 6 माह में फिर परीक्षा हो

जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की हैं

उम्मीदवारों ने इस मसले को लेकर ही जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, इस लेकर अभी स्टेटस क्या है यह सामने नहीं आया है। वहीं अभी तक आंदोलन कर रहे युवा मप्र के सभी जिलों में कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन दे चुके हैं। इससे इंदौर में भी बड़ा आंदोलन हुआ था और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था। लेकिन पूरी प्रक्रिया जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी से हुई है, ऐसे में अब भोपाल चलो नारा दिया गया है।

उधर नियुक्ति प्रक्रिया हो गई शुरू

उधर, शासन ने जून में जारी पुराने रिजल्ट को ही मान्य कर चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटवारियों की सूची भू अभिलेख आयुक्त ग्वालियर से मंजूर होकर हर जिले के कलेक्टर के पास जा चुकी है और जिले में भी 24 फरवरी को दस्तावेज सत्यापन का काम हो चुका है। अब बस नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है, जिसके लिए सीएम डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में आयोजन कराने की तैयारी की जा रही है।

सरकारी कर्मियों को वेतन देने नहीं है धन

पेज 1 का शेष

विभिन्न मंत्रालयों की फर्जी उपलब्धियां दिखाने उद्घाटन आदि के नाम से अरबों रुपए प्रतिदिन बांटकर चंगुल में रखने और अपनी मर्जी से नचा कर प्रसारण करवाने का जो पाखंड कर रही है जबकि न केवल राज्य सरकारों के विभिन्न सरकारी उपक्रमों निगम न मंडलों से लेकर सरकारी शिक्षा विभाग चिकित्सा विभागव अन्य सभी विभागों में जहां अधिकांश कंप्यूटर ऑपरेटरसे लेकर बाबू स्तर तक के कर्मचारियों का संविदा पर कार्य कर रहे इंजीनियरों डॉक्टरों व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को कई-कई विभागों में 4-6 महीने से वेतन नहीं बट रहा है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रखैल उनके मोटे फायदे मोटे ठेके देने के 19 षड्यंत्र का राज्यों में इन बातों पर उंगली ना उठे अब मुखरा जन पार्टी की राज्यों की सरकारें विशेष तौर से हाल ही में हुए तीन राज्यों के फर्जी बाड़े से जीते चुनावों के भारी भरकम परिणामों के कारण मोदी और अमित शाह की ने मिलकर अपनी मर्जी से तीनों राज्यों में ऐसे न व शिक्षव अनाड़ी नेताओं को मुख्यमंत्री बना दिया ताकि वह उनके इशारे पर नाच कर जैसा दिल्ली सरकार आदेश दे कहे वे नाच चले और जनता का पैसा लौटकर उनके हिसाब सेहर दिन दो-तीन पेज के विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में और 24 घंटे देश की हर टीवी चैनल पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरों के साथ वह अपने राज्यों में हर घंटे में 20 से 40 सेकंड के विज्ञापनों में दिखाते रहे। ताकि आने वाले चुनावों में मोदी लोकसभा सीट को जीतकर पुनः देश की सत्ता पर कब्जा कर सके।

मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत पहले ही चार लाख करोड़ के कर्ज और उसके ब्याज से गंभीर होने के बाद में भी पिछले 2 महीने में ही मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साढ़े 5000 करोड़ कर्जबाजार से उठा लिया और अपने आका की परंपराओं की तरह 50 से 80% कमिशन किचन से चार गुना की डीपीआर बनवाकर धड़ल्ले से हर दिन पूरे प्रदेश भर में उद्घाटन की बहार लाई जा रही है। यह सरकार भी जनता को भ्रमित करने और जनता की सुख समृद्धि के सब्ज बाग दिखा अपने आका की उसी लूट की परंपरा की पुनरावृत्ति कर रही है। जब कोई दूसरी तरफ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जो मजदूरी दरों में जोड़कर शंकु की दैनिक मजदूरी की दरें निर्धारित कर मजदूरों को भुगतान करने की अपेक्षा सरकारी व निजी क्षेत्रों के मजदूरों को भुगतान करने की अपेक्षा करता है। उसकी दरों को भी मध्य प्रदेश सरकार का श्रम विभाग में पालन कर नई दरों के भुगतान की व्यवस्था का परिपत्र कई वर्षों से जारी नहीं किया जा रहा। सकीना केवल पूंजीपतियों से मोटा पैसा खाकर पूंजीपतियों को सहयोग करने के साथ ही स्वयं मध्य प्रदेश की सरकार अपने सभी शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि कर बांटे।

मध्य प्रदेश के वन, शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि उद्यानिकी विद्युत मंडल की विद्युत वितरण पारेषण उत्पादन कंपनियों से लेकर लोक स्वास्थ्य यंत्र की लोक निर्माण विभाग जल संसाधन विभाग गृह निर्माण मंडल पुलिस नगर निगम पालिकाएं ग्राम पंचायतों तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी संविदा ठेका कर्मियों को केंद्र सरकार की श्रम मंत्रालय की मजदूरी भुगतान की महंगाई के अनुसार जारी की गई दर से भुगतान की बात तो बहुत दूर आने को विभागों में चार-चार महीने से वेतन नहीं दे पा रही सरकार परंतु दूसरी तरफ उसके अपने व्यक्तिगत खर्चों में सरपंचों सचिवों नेताओं पार्षदों विधायकों की मोटी कमाई के लिए ना केवल हर स्तर परखर्चों का खर्चों पर नियंत्रण की अपेक्षाधन की बर्बादी में प्रदेश सरकार और उसका मुखिया संलग्न है उसे कोई चिंता नहीं कि उसकी ही सरकार के मजदूर दैनिक वेतन भोगी संविदा एवं ठेका कर्मियों कर्मचारियों अधिकारियों हर महीने मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा अनेकों मजदूर संघों, स्वास्थ्य शिक्षा वन उद्यानिकी के मजदूरों कंप्यूटर ऑपरेटरों शिक्षकों से केंद्र सरकार की बढ़ी हुई मजदूरी धर्मपद् सरकार मानती ही नहींके साथ ही वहअपने खर्चों के कारण कर्ज में और वित्तीय गैर अनुभवी कुप्रबंधन के कारण मजदूरों की बात तो बहुत दूर महीना और सालों से अधिकांश विभागों के ठेकेदारों को भी समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है जहां तक क्षेत्रीय सरकारी जिसमें निगमों पालिकाओं पंचायतों काफी यही हाल है वहां बैठे मुख्य कार्य पालन अधिकारियों निगम आयुक्तों से लेकर चुने हुए महापौर पालिका अध्यक्ष तक सब लूटने में लगे हैं चाहे उनके कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले ना मिले।

केंद्र सरकार के जारी मजदूरी के संबंध के परिपत्र जो केंद्र सरकार की मुख्य श्रमायुक्त की साइट से डाउनलोड किए गए हैं संलग्न है।

उम्र बंधन, 1 शादी, 2 बच्चे, विच्छेद पर आधी संपत्ति, महीना भुगतान

पेज 8 का शेष

दूसरी तरफ एक हिंदू पुरुष ने हिंदू स्त्री से विवाह करने के बाद वह उसकी कमाई व पैतृक संपत्ति में विवाह विघटन पर आधी संपत्ति की वारिस हो जाती है। विरोध ब्राह्मण न्यायालय मांगस छल कपट और धोखे की अवस्था में स्त्रियों को केवल उनकी शादी के बाद प्राप्त कमाई में ही आगे का रिश्तेदार माना और पत्रक दिवस के पूर्व पश्चात कमाई संपत्ति में किसी भी हिस्से को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना।

हिंदुओं में स्त्रियों की विभव पहले 18 थी 21 कर दी गई और पुरुषों की न्यूनतम आयु को भी 21 माना जबकि वर्तमान परिदृश्य में जहां 24 घंटे 12 माह टीवी मोबाइल 12-14 साल की हिंदू स्त्री को भी उत्तेजित और यौनाकर्षण पैदा कर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाओं को जागृत कर विवश करते हैं। के विवाह को अवयस्क विवाह को कानूनी रूप से अवैध दंड का पात्र बनाते हैं वहीं दूसरी ओर उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 13 साल की मुस्लिम स्त्री 15 साल का पुरुष न केवल निकाह कर सकते हैं वरन वह जोड़ा अवयस्क होने के उपरांत भी शारीरिक संबंध बना बच्चे पैदा करने के लिए भी स्वतंत्र है। जबकि कानून रूप से हिंदुओं में ऐसे विवाह अवैध होने के साथ उसकी शारीरिक संबंध बनाने को क्रूरता का दंड का पात्र मान बलात्कार की श्रेणी का दंड संहिता में दंड देता है। इसके ऊपर भीषण संगठन आज तक कभी कुछ नहीं बोला जबकि अवैध रूप से चुपचाप संबंध स्थापित कर12 साल की उम्र की हिंदू स्त्री को भी संभोग सुख को प्राप्त करने का प्राकृतिक कृत्य मानता है। परंतु ऐसी शादी को हिंदुओं में अवैध बता स्त्री पुरुष दोनों के माता-पिता को भी दंड का भागीदार मानता तैसे यह कैसा देश है और यह कैसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है जो एक ही देश में अलग-अलग जाति के स्त्री पुरुषों पर अलग-अलग रूप से लागू होता हैके ऊपर आज तक कोई टिप्पणी लिखिए दूसरी तरफ हिंदुओं पर ऐसे कानून लागू होने पर लगातार जन्मतिथि चली आ रही है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन आरएसएस के सहयोग मोदी ने भारत की सत्ता संभालने के बाद जबकि शासन के 10 साल हो चुके हैं। हिंदुओं के संरक्षण व विकास का पाखंड करने वाली इसी आरएसएस ने हिंदुओं के साथ होते इस भेदभाव जिसमें हिंदु स्त्रियों की बदलते विश्व के संचार परिदृश्य और 24 घंटे 12 महीने मोबाइल और टीवी पर बंटते बढ़ती अश्लीलता यौनाचार दृश्यों के परोसन के कारण भारती उत्तेजकता सहचर्य की इच्छाओं के कारण स्त्रियों के विवाह की उम्र को 18 से घटाकर 15 करना चाहिए था के स्थान परउल्टे ही उसे 21 साल कर दियाजिससे अवैध यौनाचार हर स्तर पर बढ़ने के साथ यौन अपराधों में भी अत्यधिक वृद्धि होने के साथ हिंदुओं के घर गृहस्थी टूटने बिगड़ने गुजरने की समस्याएं भी बहुत आम सी हो गई है। वर्तमान परिदृश्य में हालात यह है कि हिंदू स्त्रियो 21 साल की उम्र तक विवाह न होने के कारणबाद में शिक्षा और स्वयं पैरों पर खड़े होकर कमाई करने के कारण शादियों की उम्र 25 से 35 तक चले जाने से हिंदुओं की जन्म दर में और गिरावट हुई और यह अब 1से 1.5% रह गई। यदि25 से 35 साल की उम्र में विवाह होते हैं तो वर्तमान में अधिकांश मातापिता तो यौनाचार में शीतल होने के साथ प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। जिसकी प्रणाम स्वरूप मुश्किल से ही दंपतियों में एक दो बच्चों से ज्यादा पैसा नहीं होते नहीं कर रहे दूसरी तरफ खाद पदार्थ में रसायनों के उपयोग के कारण जहां पुरुषों की वीर्य में जीवित शुक्राणु की संख्या 1910 की तुलना में मात्र 5% रह गई है। और किसके बाद यह लगातार घटती चली जाती है। के कारण अकेले इंदौर में 200 से ज्यादा परखन ली शिशु जिसमें बाहरी पुरुषों के शुक्राणु और बाहरी स्त्रियों के रजाणुओं का बाहरी निषेचन परखनली में करवा इच्छित स्त्री की कोख या किराये की कोख से पैदा करवा परिवार काम चला रहे हैं। जो पूर्णतः हिंदुओं की संरक्षक होने का पाखंड करने वाली सरकार के रहते सरकार व हिंदुओं के लिए अभिशाप बन चुका है। जब किसके विपरीत मुस्लिमों में ना केवल 13 15 साल की उम्र में निकाह हो जाने से जब तक वह स्त्री 21-22 साल की वर्ष को होती है तब तक वह 4-5 बच्चों की मां बन चुकी होती है। फिर मुसलमानों में एक से पांच शादियां तक करने की धार्मिक रूप से छूट है। यही छूट मुसलमानों की जन्म दर को हिंदुओं की जन्म दर से 10 गुना ज्यादा अर्थात 10 से लेकर 12% प्रति वर्ष है। आखिर हिंदुओं का संरक्षण करने वाली भाजपा सरकार व उसके पितृ संगठन आरएसएस जो अपने आप को हिंदुओं का संरक्षण विस्तार और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। कभी गंभीरता से सोचा ध्यान दिया की 2.5% जन्म दर से कम होने पर वह जाति धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। और उसके ऊपर कार्यवाई करने की कोशिश की नहीं कदापि नहीं।

उल्टे हौसला में रहते हुए उसकी सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमेरिकी विश्व घातक स्वास्थ्य संगठन, विश्व आतंकी व्यवसाय संगठन से मोटा कमीशन खा उन संगठनों के सदस्यों के व्यवसायों को बढ़ाने और हिंदुओं को बेरोजगार बना आत्महत्या के लिए मजबूर करने, विवाहों को लंबित कर संख्या विस्तार रोकने, खत्म करने के लिए उनके इशारों पर नाच कर 2014-15 सफाई के नाम, 2015-16 में नगदी हीन व्यवस्था बनाने हिंदु व्यापारियों उद्योग का डाटा इकट्ठा करने,8 नवंबर 2016को नोटबंदी करने, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लादने, छापने, फर्जी कोरोना बीमारी की आड में 28 महीने का तालाबंदी का नाटक कर, जिसतत्काल समय रहतेउस फर्जी वाले कारण जनता को वीडियो और लिखो से बात कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों संगठनों की, बस सरकार के उनके सार पर नाचने के षडयंत्र की चूले हिलाकर प्रदेश को 2 महीने में और देश को6 महीने में खोलने के लिए व्यवस्था कर दिया इसके विपरीत सरकार ने हजारों करोड़ की मोटी कमाई के लिए देश के अंदर कोरोना के फर्जी मौत के नंगे को लगाकर भारतीय उद्योगों व्यवसायएवं बाजारों मंडियों को खत्म करने करोड़ों पगमार्गों, ठेलो, गुमटियों, दुकानों उद्योगों पर व्यवसाय करने वाले मानसिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक नैतिक रूप से तोड़कर नष्ट करने की कोशिश की और 24 घंटे कोरोना के फर्जीवाड़े को सफल बनाने मोबाइल और टीवी समाचार पत्रों में लगातार 24 घंटे दशक बंद 5 करोड़ से ज्यादा हिंदू पहली दूसरी लहर मार डालने के साथ श्मशान घाटों में लाइन लगाकर शवों से सबका मौतों का उत्सव मना हिंदुओं को ही नष्ट किया गया। देश का 90% मुसलमानना तो सरकार के फर्जी भय में आया ना उसने कोरोना के नियम माने। न ही सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों पुलिस को उन्होंने कोरोना के समय अपने मोहल्ले में घुसकर सबको बंद करने की साजिश को सफल होने दिया ना ही उसने सभी प्रकार के सरकारी डर व दबाव के सामने नतमस्तक हो मानने की अपेक्षा 90% मुसलमानों ने पीक लगवाए और मजबूरी में टीका लगवाने की अपेक्षा उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर अपने स्वास्थ्य व सरकारी कार्यों को संपन्न किया 1रु किलो का गेहूं रु.2 किलो का चावल व अन्य सेवाएं भी भरपूर प्राप्त की। वर्तमान हालात यह है जिन लोगों ने स्कूलों से लेकर बुजुर्गों तक टीका लगवाया वे धड़ाधड़ मौत का शिकार होकर प्रतिदिन लगभग 5 लाख हिंदुओं की टीके से अकाल मौत हो रही है। इस प्रकार कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 5 करोड़ हिंदू मारे और 8 करोड़ से ज्यादा हिंदू टीका लगने से अभी तक अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। जिसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा और उसका पितृ संगठन जिम्मेदार है। क्या यही सनातनियों और हिंदुओं के संरक्षण करने वाली सरकार है। जो स्वयंही भस्मासुर बन उनके सिर पर हाथ रख करोड़ों लोगों की मौत का तांडव कर चुकी है और कर रही है। फिर कहां गया एक देश सभी के लिए एक समान कानून, समान आचार व नागरिक संहिता। सब सनातनियों को भ्रमित कर उनके नष्ट करने के षड्यंत्र का हिस्सा है। जिसमें बुकाबन पार्टी और आरएसएस बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा पैसा खाकर हिंदुओं के खत्म करने के षड्यंत्र में हर कदम आहुति डाल रहे हैं जहां तक मंदिरों का निर्माण और विकास का सवाल है वहीं सारे प्राचीन ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों को तीर्थ स्थल की श्रेणी से बाहर निकाल पर्यटन, मनोरंजन और अय्याशी स्थल बना उनसे मोटी कमाई करने के लिए विकसित किया जा रहे हैं और यह कैसा कौन सा कानून है? जो के हिंदुओं के धर्मस्थलों संपत्तियों दान की प्राप्तियों को सरकार की धर्मस्व आय का साधन मान उस धन को मुसलमानों को हज पर भेजने में खर्च करने के साथ कभी 56 इंची की औकात हुई तो मुसलमानों की मस्जिदों ईसाइयों के चर्चों पर सरकारी नियंत्रण कर उनकी आय को अपनी बना सके या केवल यह सारा बहादुरी का पाखंड डरपोक हिंदू भेड़ों के लिए ही है।

सारे नियम कानून छोटे दुकानदारों उद्योगों पर थोप नष्ट करने का षड्यंत्र

पेज 8 का शेष

10000 करोड़ रु पशु चिकित्सा विभाग में दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए खर्च किए, तो क्या एक करोड़ दुधारू पशुओं का जन्म हुआ अर्थात 1 लाख में भी एक दुधारू पशु पैदा हुआ।

यदि खर्च किए गए बजट के हिसाब से रु. 100000 में भी एक पशु पैदा करवा देते तो एक करोड़पशुहर वर्ष प्रदेश को मिलते। स्वाभाविक था दूध की नदियां बह सकती थी। फिर गौमांस और जीवित दुधारू पशु क्या किसानों ने निर्यात करवाना शुरू कर दिये? उसको भी तो मोदी सरकार ही कर रही है ना। फिर भारत से ही क्यों लाखों दुधारू पशुओं का निर्यात हो रहा है? चलो किसानों की टंकी से व वाहनों से, डेरी दूध विक्रेताओं को खत्म करने के लिए आप सारे सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खासतौर से मोदी के गुजरात की अमूल और प्रदेश की सांची को बढ़ावा देने मनमानी कीमतें लूटना है। कृषि विभाग में दुग्ध उत्पादकों को भी किसान ही माना जाता है। कृषि में पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय जिसमें बकरी दुधारू पशुओं के साथ कुक्कुट मत्स्य पालन, रेशम कीट उत्पादन को भी कृषि कार्य में सहायक गतिविधियां मानी जाती है।

कल के दिन सब्जी उत्पादक किसानों से बोलना की सब्जी को पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह पैक करो। उस पर उसकी कैलोरी लिखो उसके नुकसान फायदे लिखो। उत्पादन की तारीखऔर समय बाधित होने की तारीख लिखो। फिर आढतिये या बचने के लिए मंडी में लाओ। और नहीं कर सकते हो। तो खेतो की जमीन बेच कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दो।

वह सब कुछ कर लेंगे क्योंकि उनसे उन कलेक्टर कमिश्नर खाद्य सुरक्षा अधिकारी से लेकर मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक को महीना मिलता है। और गरीब किसान कुछ नहीं दे सकताइसलिए सारी जमीन बेचकर रु. 1 किलो का गेहूं, रु.2 किलो का चावल खाओ जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में व्यवस्था की गई है। ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और मोदी के पूंजी मित्रों को रु. 5000-7000 महीने में सस्ते श्रमिक मिल सके और जो सक्षम है। उनको भी 10 रू किलो का आलू रु.100 किलो में रु. 50 किलो की लहसुन रु. 800 किलो में बेच जनता को लूटा जा सके। कहानी शुरू हुई थी कि दुग्ध उत्पादक किसानों व उनके टंकी से व छोटे विक्रेताओं डेरी वालों को दूध पर फेट व एस एन एफ लिखना अनिवार्य है। वैसे भी भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी जो इंदौर में मोटी रायल्टी पर जो करोड़ों, मासिक इएमआइ पर पदस्थ किये जाते हैं। आते ही साथ अवैध कॉलोनी के नाम पर कालोनियां नहीं तोड़ेंगे, सौंफ के रंगीन करने के कारण फैक्ट्रीयां नहीं तोड़ेंगे, दूध दही वालों से लेकर, स्मार्ट सिटी के नाम पर बाजारों की तोड़फोड़ करनेदुकान बर्बाद करने व्यवसाय चौपट करने के बाद में भी यातायात सुधारने के नाम पर एक तरफा यातायात कर व्यवसाय चौपट करने का षड्यंत्र नहीं करेंगे। तो वसूली कैसे और कहां से होगी?

फिर टंकी व डेरी वालों के दूध पर सब कुछ लिखना अनिवार्य कर दिया। परंतु सहकारिता में चलने वाली सांची और अमूल के नमूने 1984 से नहीं लिए, न ही उस दूध की जांच करवाई यह बात स्वयं सरकार ने 2006 में विधान सभा में स्वीकार की थी।

दूसरी तरफ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की माने तो यदि सांची और दूध के नमूने लेने की जिसने भी कोशिश कीउसको सीधा कलेक्टर जो कि सभी सहकारी समितियों का अध्यक्ष होता हैकलेक्टर ने नौकरी से हटा देने की धमकी दीजब मूल का मामला उठा तो सीधा टेलीफोन प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रहा है 10 साल से, दूसरी तरफ इन हरामखोर जालसाजो नए सभी निजी खाद्य पदार्थों की जांच करने और विश्लेषण करने वाली प्रयोग शालाओं के मालिकों को स्पष्ट ढंग से चेतावनी दे रखी हैकी कोई भीसांची और अमूल के दूध की जांच नहीं करेगा? क्या कानून अपने बाप की जागीर है, जबकि नकली दूध के टैंकर जो सांची में सप्लाई हो रहे थे वह पकड़े गए, थे। उनकी आज तक जांच फाइलों में इंतजार ही कर रही है। जब जानकर ही नहीं है तो अकेले मध्य प्रदेश में ही सांची और अमूल जैसा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया की 90% दूध जनता को आपूर्ति की जा रही है वह आयातित पाउडर का शुद्ध मिश्रण होने के बाद में भी सांची और अमूल अपने पैकेट पर शुद्ध गाय का ताजा दूध अवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से लिख रहे हैं। क्योंकि गांवों से किसानों से दूध इकट्ठा करने, लाने फिर उसको संयंत्र में उसकी फेट निकाल उसमें आयातित बटर आइल मिला उसमें गोल्ड की पैकिंग में भी 2 से 3% फेट मिलाई जाती है जबकि लिखा 6 से 8% जाता है।

फिर वह सहकारी समिति, जहां बैठे अधिकारी कर्मचारी जो वर्षों से कुंडली मारे बैठे हैं। भारी भ्रष्ट है। जो खरीदी बिक्री में, प्लांट मेंटिनेंस से लेकर दूध की पैकिंग और आपूर्ति में भी भारी भ्रष्टाचार करते हैं। जितने भी सहकारिता में चुने हुए अध्यक्ष से लेकर उन सदस्य बढ़ाए जाते हैं सबको अपना हिस्सा चाहिए रहता है। स्वाभाविक हैइस भर उपभोक्ता को बढ़ाने पर भी शुद्ध दूध नहीं मिलता है।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर लिखित जवाब देते हैं सहकारिता में सूचना का अधिकार के पत्र का जवाब देना बाध्यता नहीं है। इतने सारे षड्यंत्र और भ्रष्टाचार सारी सरकारी अधिकारी कर्मचारी करे परंतु उनकी कोई जवाबदारी नहीं है जनता भर मूर्ख है। जो इन सबको हर तरह से लुटकर भी पाले पोसे भ्रष्टाचार करने के अवसर प्रदान करे और जानवरों की तरह रोते हुए जीती रहे। जो पंजाब हरियाणा की किसान आंदोलन कर रहे हैं वही आंदोलन पूरे देश के हर सरकारों के खिलाफ और खासतौर से जहां भेड़िया ढूंढ पार्टी की सरकार है। कर, कर अपने अधिकारों की रक्षा किसानों छोटे व्यापारियों उद्योगपतियों बाजारों मंडियों को पूरे देश में करना पड़ेगी। अन्यथा यह सब बहुराष्ट्रीय कंपनी के सारे पढ़ना आज कल आपको गुलामों की तरह भिखारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नाकिया बोले आंदोलन बल्कि वकीलों की पूरी टीम किसानों को अपने साथ में रखनी चाहिए, जोइन सभी अधिकारियों केऊपर भ्रष्टाचार जलसा जील छल कपट शासन के जन धन की बर्बादी पर भारतीय दंड संहिताओं की धारा 120 बी 216, 218, 198, 199 व अन्य धाराओं में कानून के अंतर्गत सत्र व जिला न्यायालयों में केस लगाकर घेर कर रखें। और जैसे ही सरकारी अधिकारी कर्मचारी निरीक्षकों के खिलाफ अगर हर महीने में एक दो भारतीय प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को पूरे देश भर में भी सजा हो गई। तब ही सुधरेंगे।

इसको सभी व्यापारी गणों के, उद्योगों के संघ किसानों के संगठनों विभिन्न कानूनों के अंतर्गत न्यायालयीन कार्यवाहियों को सबसे पहले शुरू कर देना चाहिए।

अन्यथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का महीना खाकर उनके व्यवसाय के लिए 10 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारियों दुकानदारों विक्रेताओं उद्योगों, 15 करोड़ किसानों का अस्तित्व समाप्त कर सारे व्यापार उद्योग खेती किसानी दुग्ध मांस मछली उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपना ही इनका परम उद्देश्य है।

यह बात सन 2006 से मैं लगातार लिख, कह, समझा व बता रहा हूं? बिना सड़कों पर निकले और कानूनी कार्यवाई किए आपको इन जालसाजियों षड्यंत्रों से निजात जीवन पर्यंत नहीं मिलेगी।

इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जरूर यह है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कठपुतली भेड़ियों को भगाओ।

हिंदुओं के संरक्षण का पाखंड करने वालों की सरकार

उम्र बंधन, 1 शादी, 2 बच्चे, विच्छेद पर आधी संपत्ति, महीना भुगतान

सत्ता में रहते सबसे ज्यादा लूट, हिंदुओं की बर्बादी, मौतों का तांडव, जन्म दर में गिरावट से समाप्ति की ओर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. केशव हेडगेवार द्वारा की गयी थी।

सबसे पहले 50 वर्ष बाद 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केन्द्र में मोरारजी देसाई के प्रधानमन्त्रित्व में मिलीजुली सरकार बनी। 1975 के बाद से धीरे-धीरे इस संगठन का राजनैतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे राजनैतिक दल के रूप में हुई जिसे आमतौर पर संघ की राजनैतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। संघ की स्थापना के 75 वर्ष बाद सन 2000 में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की मिलीजुली सरकार भारत की केन्द्रीय सत्ता पर आसीन हुई।

अंग्रेजों ने अपने राज्य काल में ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदुओं के शोषण व भ्रमित करने उच्च शब्दावली का प्रयोग करते हुए रॉयल सोशल सर्विस के नाम से संस्था बनाई और चुपचाप हिंदुओं के विग्गज धूर्तों को अंतरित कर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में स्थापित की गई। जिसे अंग्रेज प्यार से रॉयल सिक्रेट सर्विस के नाम से भी पुकारते थे। जैसा की दस्तावेजों अध्ययन से प्राप्त हुआ। जो अंग्रेजों को कांग्रेस व अन्य क्रांतिकारी संगठनों के आजादी के आंदोलन के विपरीत आंदोलनकारियों के दमन व खत्म करने के लिये सूचनाएं व सलाह देती थी। इसके बदले में उसके अनेकों सदस्यों को अंग्रेज पेंशन देते थे। यह एकमात्र ऐसा विश्व का संगठन है जो अभी तक किसी भी कानूनी रूप से सरकारी दस्तावेजों में किसी भी संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं है।

यह संस्था हिंदुओं को संगठित करने अनुशासन, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, परंपराओं के नाम पर पूंजीपतियों व सक्षम सदस्यों से दान लेकर कार्य हिंदुओं को संगठित करने संरक्षित करने का पाखंड कर रही है। क्योंकि उसके रहते हुएआजादी के बाद भी अधिकांश कानून जिसमें हिंदु विवाह अधिनियम 1955, जिसकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई है। हिन्दू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा सन 1955 में पारित एक विधि है। इसी कालावधि में तीन अन्य महत्वपूर्ण विधियाँ पारित हुईं : हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956। ये सभी नियम हिन्दुओं के वैधिक परम्पराओं को आधुनिक बनाने के ध्येय से लागू किए गये थे।

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार न्यायिक पृथक्करण निम्न आधारों पर न्यायालय से प्राप्त हो सकता है :

त्याग 2 वर्ष, निर्दयता शारीरिक एवं मानसिक, कुष्ट रोग 1 वर्ष, रतिजरोग 3 वर्ष, विकृतिमन 2 वर्ष तथा परपुरुष अथवा पर-स्त्री-गमन एक बार में भी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार - संसर्ग, धर्मपरिवर्तन, पागलपन 3 वर्ष, कुष्ट रोग 3 वर्ष, रतिज रोग 3 वर्ष, संन्यास, मृत्यु निष्कर्ष 7 वर्ष, पर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पास होने के दो वर्ष बाद तथा दाम्पत्याधिकार प्रदान करनेवाली डिक्री पास होने के दो साल बाद 'सम्बन्धविच्छेद' प्राप्त हो सकता है।

स्त्रियों को निम्न आधारों पर भी संबंधविच्छेद प्राप्त हो सकता है, यथा-द्विविवाह, बलात्कार, पुंमैथुन तथा पशुमैथुन। धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत न्यायालय 'विवाहशून्यता' की घोषणा कर सकता है। विवाह प्रवृत्तिहीन घोषित किया जा सकता है, यदि दूसरा विवाह सपिण्ड और निषिद्ध गोत्र में किया गया हो धारा 11।

नपुंसकता, पागलपन, मानसिक दुर्बलता, छल एवं कपट से अनुमति प्राप्त करने पर या पत्नी के अन्य पुरुष से (जो उसका पति नहीं है) गर्भवती होने पर विवाह विवर्ज्य घोषित हो सकता है। धारा 12।

अधिनियम द्वारा अब हिन्दू विवाह प्रणाली में निम्नांकित परिवर्तन किए गए हैं :

☐ 1 अब हर हिन्दू स्त्री-पुरुष दूसरे हिन्दू स्त्री-पुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो।

☐ 2 एकविवाह तय किया गया है। द्विविवाह अमान्य एवं दण्डनीय भी है।

☐ 3 न्यायिक पृथक्करण, विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद तथा विवाहशून्यता की डिक्री की घोषणा की व्यवस्था की गयी है।

☐ 4 प्रवृत्तिहीन तथा विवर्ज्य विवाह के बाद और डिक्री पास होने के बीच उत्पन्न सन्तान को वैध घोषित कर दिया गया है। परन्तु इसके लिए डिक्री का पास होना आवश्यक है।

☐ 5 न्यायालयों पर यह वैधानिक कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में समाधान कराने का प्रथम प्रयास करे।

☐ 6 बाद के बीच या सम्बन्धविच्छेद पर निर्वाह-व्यय एवं निर्वाह भत्ता की व्यवस्था की गयी है। तथा

☐ 7 न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख रेख एवं भरण पोषण की व्यवस्था करे।

यह संस्था हिंदुओं को संगठित करने अनुशासन, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, परंपराओं के नाम पर पूंजीपतियों व सक्षम सदस्यों से दान लेकर कार्य हिंदुओं को संगठित करने संरक्षित करने का पाखंड कर रही है। क्योंकि उसके रहते हुएआजादी के बाद भी अधिकांश कानून जिसमें हिंदु विवाह अधिनियम 1955, जिसकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई है।

अब यह कानून हिंदू स्त्रियों के लिए पुरुषों के शोषण का हथियार व अधिकार बन चुका है। जबकि मुस्लिमों में मुस्लिम पुरुष केवल बोल कर ही आसानी से निकाह करके तीन तलाक से खत्म करने के साथ प्रतीक्षा स्त्री को किसी भी प्रकार के बच्चों को पालने को जीवन यापन खर्च देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बेशक मोदी सरकार ने तीन तलाक को अवैध बना दिया है।

(शेष पेज 7 पर)

विश्व स्वास्थ्य घातक व व्यावसायिक आतंकी संगठन के इशारे पर नाच

सारे नियम कानून छोटे दुकानदारों उद्योगों पर थोप नष्ट करने का षड्यंत्र

सभी व्यावसायिक उत्पादक किसान संघों को एकत्रित हो सड़कों पर उतर व कानून से अस्तित्व बचा जनहितों की रक्षा करनी होगी

भारत में मोदी के सत्ता संभालने के बाद पूरी भुखेरा जन पार्टी बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर नाच उनसे मोटा कमीशन वसूल कर भारतीय 10 करोड़ से ज्यादा व्यवसाईयों उद्योगों जिनमें 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्वरोजगार के साथ मजदूरी पर कार्यरत हैं। को संरक्षण देने कानूनी संरक्षण देने प्रोत्साहित करने की अपेक्षा नष्ट करने पर तुली है। उल्टे हीसत्ता में रहते हुए उसकी सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमेरिकी विश्व घातक स्वास्थ्य, आतंकी व्यवसाय संगठन से मोटा कमीशन खा उन संगठनों के सदस्यों के व्यवसायों को बढ़ाने और हिंदुओं को बेरोजगार बना आत्महत्या के लिए मजबूर करने, विवाहों को लंबित कर संख्या विस्तार रोकने, खत्म करने के लिए उनके इशारों पर नाच कर 2014-15सफाई के नाम, 2015-16 में नगदीहीन व्यवस्था बनाने हिंदु व्यापारियों उद्योग का डाटा इकट्ठा करने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करने, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लादने, थोपने, फर्जी कोरोना बीमारी की आड़ में 28 महीने का तालाबंदी का नाटक कर, जिसेतत्काल समय रहतेउसे फर्जी वाले का सच जनता को वीडियो और लिखो से बात कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों संगठनों की. बस सरकार के उनके सारे पर नाचने के षडयंत्र की चूलें हिलाकर प्रदेश को 2 महीने में और देश को 6 महीने में खोलने के लिए व्यवस्था कर दिया इसके विपरीत सरकार ने हजारों करोड़ की मोटी कमाई के लिए देश के अंदर कोरोना के फर्जी मौत के तड़के का लगाकर भारतीय उद्योगों व्यवसाय एवं बाजारों मंडियों को खत्म करने करोड़ो पगमार्गी, ठेलों, गुमटियों, दुकानों उद्योगों पर व्यवसाय करने वाले मानसिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक नैतिक रूप से तोड़कर नष्ट करने की कोशिश की और 24 घंटे कोरोना के फर्जीवाड़े को सफल बनाने मोबाइल और टीवी समाचार पत्रों में लगातार 24 घंटे दशक बंद 5 करोड़ से ज्यादा हिंदु की हत्या कर 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार बना चुकी है। किस कानून में लिखा हुआ है। ताजा दूध बेशक नकली या रसायनों से बना हुआ है। क्योंकि देश की 140 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ भी दुधारू गाय भैंस नहीं है। कभी राजके पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग से पूछा की हजारों करोड़ का बजट खाने के बाद में भी आखिर गाय भैंस के प्रजनन और संख्या बढ़ाने का कार्य क्यों नहीं संपन्न हो रहा है जबकि अरबों रु का जर्सी सांडो और पाड़ो के वीर्य आयात और रखरखाव पर खर्च किए जाते हैं। (शेष पेज 7 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958